



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

24 ज्येष्ठ 1940 (श0)  
(सं0 पटना 566) पटना, वृहस्पतिवार, 14 जून 2018

---

सं० एम-4-53/2007-4443/वि०

वित्त विभाग

संकल्प

14 जून 2018

**विषय :- स्कीमों की स्वीकृति हेतु शक्तियों का प्रत्यायोजन ।**

दिनांक 01.04.2017 से योजना एवं गैर योजना स्कीमों का विलय हो जाने के कारण मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या-306, दिनांक 17.03.2017 द्वारा वित्तीय मामलों में प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के आलोक में वित्त विभागीय संकल्प संख्या-3758, दिनांक 31.05.2017, 4573, दिनांक 04.07.2017 एवं 8236 दिनांक 17.10.2017 द्वारा स्कीमों की स्वीकृति हेतु शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया है ।

2. वित्त विभागीय संकल्प संख्या-3758, दिनांक 31.05.2017 की कंडिका-8 में संकल्प सं0-4573, दिनांक 04.07.2017 द्वारा प्रावधानित किया गया है कि **स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय (पूर्व में गैर योजना) मद में ऋण/सहायक अनुदान (विवेकानुदान सहित)/सब्सिडी से संबंधित चालू स्कीमों की प्रत्येक वर्ष स्वीकृति कंडिका-4(क) के समान होगी किन्तु स्थानीय निकायों (शहरी स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं) को अनुदान के रूप में दी जाने वाली राशि की स्वीकृति प्रशासी विभाग वित्त विभाग की सहमति से दे सकेगा, बशर्ते बजट में राशि का प्रावधान हो ।**

3. राज्य सरकार के अधीन शहरी स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं के अतिरिक्त भी ऐसी संस्थाएं हैं जैसे विश्वविद्यालय, अल्पसंख्यक विद्यालय इत्यादि, जिन्हें प्रतिवर्ष स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद के अंतर्गत वेतनादि हेतु सहायक अनुदान दिया जाता है । ध्यातव्य है कि इन संस्थाओं का वित्त पोषण बजट में प्रावधानित रहता है । स्थापना एवं प्रतिबद्ध मद के अंतर्गत अन्य व्यय हेतु मंत्रिपरिषद की स्वीकृति विहित नहीं है । अतः उपरोक्त प्रावधान में संशोधन की आवश्यकता प्रतीत हो रही है ।

4. उपरोक्त के आलोक में संकल्प सं0-4573, दिनांक 04.07.2017 द्वारा वित्त विभागीय संकल्प संख्या-3758, दिनांक 31.05.2017 की कंडिका-8 में किये गये उपरोक्त प्रावधान को निम्न से प्रतिस्थापित किया जाता है :-

“स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय (पूर्व में गैर योजना) मद में ऋण/सहायक अनुदान (विवेकानुदान सहित)/सब्सिडी से संबंधित चालू स्कीमों की प्रत्येक वर्ष स्वीकृति कंडिका-4(क) के समान होगी किन्तु स्थानीय निकायों (शहरी स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं), राज्य सरकार के अधीन गठित स्वशासी निकाय, जैसे विश्वविद्यालय आदि अथवा मात्र वेतनादि अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाओं को वेतनादि एवं वेतनादि के अलावा (पेंशन) मद में सहायक अनुदान के रूप में दी जाने वाली राशि की स्वीकृति प्रशासी विभाग वित्त विभाग की सहमति से दे सकेगा, बशर्ते बजट में राशि का प्रावधान हो।”

5. संकल्प में निर्धारित अन्य व्यवस्थायें यथावत् रहेंगी।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

राहुल सिंह,  
सचिव(व्यय)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 566-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>